

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०--------डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग\_4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 3 अक्टूबर, 2022 आश्विन 11, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2

संख्या 882/आठ-अ०जि०अ० (भू०अ०) / सं०सं० / मेरठ लखनऊ, 3 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

#### प० आ०-662

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेष सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देष्य हेतु) राय है, कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (रैपिड रेल) परियोजना हेतु जनपद मेरठ, तहसील सदर परगना सरावा/मेरठ के ग्राम अमीनगर उर्फ भूडबराल, बरालपरतापुर, मोहकमपुर, मेरठ खास, हाफिजाबाद मेवला एवं तहसील सरधना के क्षेत्र/ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, रोषनपुर डोरली, व दुल्हैडा चौहान में कुल 5.898246 हे0 भूमि की आवष्यकता है।

2—राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुषंसा प्रस्तुत की गयी है।

3-सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांष इस प्रकार है-

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (रैपिड रेल) परियोजना के निमित्त जनपद मेरठ में भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना जनहित में है और इससे लोकप्रयोजन की पूर्ति होती है। परियोजना से तीव्र एवं सुरक्षित तथा सस्ता परिवहन तंत्र विकसित हो सकेगा। इस परियोजना से संभावित लाभ, सामाजिक खर्च एवं प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में कहीं अधिक है। परियोजना के आवष्यक कुल भूमि मूल्य के सापेक्ष अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अत्यन्त कम है।

लिए	4—भूमि अर्जन के कारण कुलशून्यपरिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के अपरिहार्य कारण निम्नवत् है :—
	ड्पटी कलेक्टर / असिस्टेंट कलेक्टरशून्यशून्य
	को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देष्य से प्रषासक नियुक्त जाता है।
	5—अतः समुचित सरकार सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य
सूचन	ा हेत् अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

### अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
मेरठ	सदर		अमीनगर उर्फ भूडबराल	163	0.3600
				164	0.3170
				466	1.2740
				468	0.0885
			बराल परतापुर	334	0.0380
				335	0.0350
				336	0.1121
				337	0.1275
				338	0.0909
				861	0.0756
				863	0.0312
				866	0.0284
				750	0.0863
				751	0.2133
				755	0.0213
				760	0.1581
				770	0.1307
			मोहकमपुर	488	0.0831
				489	0.0264
				490	0.0995
				491	0.0006
				493	0.3438
				494	0.1488
			मेरठ खास	2038	0.1585
			_	1237	0.1170
				1228	0.1469
			हाफिजाबाद	83	0.373
			मेवला	71	0.923

1	2	3	4	5	6	
मेरठ	सरधना		मुकर्रबपुर पल्हैडा	54	0.0850	
				89	0.6005	
				461	0.086074	
				462	0.015859	
				463	0.003057	
				464	0.067287	
				465	0.001824	
				466	0.011135	
			रोशनपुर डोरली	133	0.0220	
					134	0.0205
						135
				136	0.0062	
			664	0.0494		
			665	0.0527		
				666	0.0535	
				668	0.00971	
				663/2	0.0396	
		दुल्हैडा चौहान		822	0.0793	
				823	0.0917	

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देती हैं।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो, अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपित्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से, दीपक मीणा, समुचित सरकार/जिला कलेक्टर, मेरठ।

#### No. 882/VIII-A.Ji.A.(Bhu.A.)/San.San./Meerut

Dated Lucknow, October 3, 2022

UNDER sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 5.898246 Hectares of land is required in the village Aminagar *Urf* Bhudbaral, Baralpartapur, Mohkampur, Meerut Khas, Hafijabad Mewla Tehsil Sadar Mukarrabpur Palhera, Roshanpur Daurli, Dulhera Chauhan Tehsil Sardhana, District Meerut is required for public purpose, namely, project "implementation of Delhi-Gzb-Meerut RRTS Corridor" through National Capital Region Transport Corporation (NCRTC).

- 2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment agency and submits its recommendation to the Appropriate Government.
  - 3. The summary of the Social Impact Assessment Report as follows:-

Taking action for land acquisition in Meerut district for the purpose of Rapid Rail (NCRTC) is in the public interest and it serves the public purpose. The project will develop a faster, safer and cheaper transport system. The potential benefits from this project far outweigh the social costs and adverse social impacts. The land proposed for acquisition is very less relative to the total land value required for the project.

4. A total ofNILfamilies are lik	ely to be	e displaced	due to	the land	acquisition.	The
reason necessitation such displacement is as under:-						
NIL,				Deputy C	Collector/Assi	stant

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purposes.

#### **SCHEDULE**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar		Aminagar Urf	163	0.3600
			Bhudbaral	164	0.3170
				466	1.2740
				468	0.0885
		Baral Partapur	334	0.0380	
				335	0.0350
				336	0.1121
				337	0.1275
				338	0.0909
			861	0.0756	
				863	0.0312
			866	0.0284	
				750	0.0863
				751	0.2133

1	2	3	4	5	6
Meerut	Sadar		Baral Partapur	755	0.0213
			_	760	0.1581
				770	0.1307
			Mohkampur	488	0.0831
				489	0.0264
				490	0.0995
				491	0.0006
				493	0.3438
				494	0.1488
			Meerut Khas	2038	0.1585
				1237	0.1170
				1228	0.1469
			Hafijabad Mewla	83	0.373
				71	0.923
	Sardhana	Mukarrabpur Palhera	Mukarrabpur Palhera	54	0.0850
				89	0.6005
				461	0.086074
			462	0.015859	
		463	0.003057		
			464	0.067287	
				465	0.001824
				466	0.011135
			Roshanpur Daurli	133	0.0220
				134	0.0205
				135	0.1608
				136	0.0062
				664	0.0494
				665	0.0527
				666	0.0535
				668	0.00971
				663/2	0.0396
			Dulhera Chauhan	822	0.0793
				823	0.0917

- 6. The Governor is also pleased to authorize the Collector for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon and survey of the land, take levels of any land, dig subsoil into the sub oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.
- 7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 days after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.
- 8. Under section 11 (4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.*, sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

**Note:-**A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

By order,
DEEPAK MEENA,
Appropriate Government/Collector,
Meerut.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 763 राजपत्र—2022—(1163)—599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 7 सा० आवास एवं शहरी नियोजन—2022—(1164)—150 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।